

राजस्थान सरकार
कार्मिक विभाग
क-28

क्रमांक:-एफ 158/कार्मिक/क-2/75

जयपुर, दिनांक 4 जनवरी, 96

आज्ञा

विषय:- अधिवार्त्तिकी आय प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा में वृद्धि एवं पुनर्नियुक्ति ।

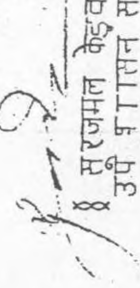
इस विभाग की समसंख्यक आदेशा दिनांक 6 अप्रैल, 1978 प्रति संलग्न द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जनहित में किसी अधिकारी/कर्मचारी को पंजी-गण्डल की पूर्व स्वीकृति के पश्चात् उसकी अधिवार्त्तिकी आय के बाद् सेवा में वृद्धि कर अथवा पुनर्नियुक्ति कर रखा जा सकेगा । उक्त आदेशा राज्य के विभिन्न उपक्रमों, कम्पनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं एवं स्थायत्तशासी संस्थाओं इत्यादि में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामलों पर भी समान स्प से लागू होने संबंधी स्पष्टीकरण इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 6.10.78 द्वारा जारी किया गया ।

सेवा वृद्धि एवं पुनर्नियुक्ति के मामलों पर विचार करने के लिए इस विभाग के समसंख्यक आदेशा दिनांक 25.2.76 प्रतिलिपि संलग्न द्वारा

कुछ मापदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित की थी लेकिन इस विभाग के ध्यान में आया है कि प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्षों द्वारा उक्त प्रक्रिया की पालना नहीं की जा रही है और सेवा वृद्धि या पुनर्नियुक्ति के मामले इस विभाग को सहमति हेतु दस्तूरी लम्ब में भेजे जा रहे हैं। मंत्रीमण्डल की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा में वृद्धि एवं पुनर्नियुक्ति कर दी जाती है। राज्य सरकार ने इसे गभीरता से लिया है।


अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों का ध्यान पुनः इस विभाग के समसंख्यक आदेशा दिनांक 25.2.76 को ओर आकर्षितकर तथादिष्ट किया जाता है कि सेवा वृद्धि या पुनर्नियुक्ति के मामलों को विद्यमान निर्देशों के अनुस्यू परीक्षण करने के पश्चात् ही इस विभाग की सहमति हेतु भेजने का कट करें।

आज्ञा से,


सुरजमल कडवाल
उप प्रशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य, राज्यपाल/मुख्यमंत्री।
2. मुख्य, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री/मुख्य सचिव।
3. समस्त प्रशासन सचिव/विशेष ट प्रशासन सचिव/उप प्रशासन सचिव।
4. सचिवालय के समस्त विभाग/गप/प्रकोष्ठ।
5. समस्त विभाग अध्यक्ष/सभागिनियुक्त/जिला-कलेक्टर सहित।


उप प्रशासन सचिव